



2026:AHC: 124949-DB

18.02.2026 को सुरक्षित

03.06.2026 को पारित

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक अपील संख्या - 4031/2010

शेरपाल

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : जय सिंह चंदेल, कंचन रंजन, आर. डी. डौहोलिया

प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 44

माननीय न्यायमूर्ति सिद्धार्थ

माननीय न्यायमूर्ति हरवीर सिंह

(माननीय न्यायमूर्ति हरवीर सिंह द्वारा प्रदत्त)

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री अश्वनी कुमार ओझा, और राज्य-प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम श्रीमती मंजू ठाकुर को सुना गया तथा अवर न्यायालय के अभिलेखों और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश का परिशीलन किया गया।

2. वर्तमान आपराधिक अपील विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 7, बुलंदशहर द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 1142/2008 में पारित निर्णय और आदेश दिनांक 27.04.2010 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। यह विचारण पुलिस स्टेशन औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 176/2008, धारा 302 और 307 भारतीय दंड संहिता, 1860 से उत्पन्न हुआ था।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



जिसके द्वारा, अपीलकर्ता को आई.पी.सी. की धारा 302 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और 10,000/- रुपये के जुर्माने के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि 28.06.2008 को, सूचनादाता किशनचंद, निवासी ग्राम मूढी बकापुर, पुलिस स्टेशन औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर ने पुलिस स्टेशन औरंगाबाद के थानाध्यक्ष (एस.एच.ओ.) को एक लिखित शिकायत (प्रदर्श क-1) प्रस्तुत किया। शिकायत में कहा गया था कि अभियुक्त शेरपाल, पुत्र अमीचंद, जो उसी गांव का निवासी है, एक बुरे चरित्र का व्यक्ति और आवारा था। बताया गया कि अभियुक्त सूचनादाता की पुत्री सीमा (अब मृतका) पर बुरी नजर रखता था और अतीत में उसके साथ छेड़छाड़ कर चुका था, जिसके लिए उसने सार्वजनिक रूप से माफी मांगी थी। 28.06.2008 को सीमा अपने भाई संजीव (उम्र लगभग 10 वर्ष) और बहन अंजू (उम्र लगभग 12 वर्ष) के साथ अपने खेत में चारा काटने गई थी। जब वे काम कर रहे थे, तब अभियुक्त शेरपाल एक देशी तमंचे से लैस होकर खेत में पहुंचा। दुर्भावनापूर्ण इरादे से, उसने सीमा को पकड़ लिया और उसे ज्वार के खेत की ओर खींचने लगा। जब सीमा और उसके भाई-बहन ने शोर मचाया, तो पड़ोसी खेतों में काम कर रहे वीरपाल पुत्र चंद्रपाल और रमेश चंद पुत्र मल्ली सिंह उसे बचाने के लिए दौड़े। अपने प्रयास को विफल होते देख, अभियुक्त शेरपाल ने सीमा के पेट में गोली मार दी और उत्तर दिशा के खेतों की ओर भाग गया। जब गवाहों ने उसे पकड़ने के लिए पीछा किया, तो अभियुक्त ने उन पर गोलियां चलाई और हवा में अपना तमंचा लहराते हुए भागने में सफल रहा। पूरी घटना को दो पड़ोसियों के साथ-साथ घायल सीमा के भाई और बहन ने देखा था। बुलंदशहर अस्पताल ले जाते समय, स्याना बस स्टैंड के पास सीमा की चोटों के कारण मृत्यु हो गई।

4. सूचनादाता किशनचंद द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत (प्रदर्श क-1) के आधार पर, अभियुक्त-अपीलकर्ता शेरपाल के विरुद्ध पुलिस स्टेशन औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर में धारा 302 और 307 भारतीय दंड संहिता, 1860 के अंतर्गत अपराध संख्या 176/2008 के रूप में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज की गई। विवेचना शुरू में श्री कन्हैयालाल चौधरी, थानाध्यक्ष, पुलिस स्टेशन औरंगाबाद द्वारा की गई, और बाद में इसे श्री बलवीर सिंह, थानाध्यक्ष, पुलिस स्टेशन औरंगाबाद ने अपने हाथ में ले लिया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



5. चक्षुदर्शी और अन्य गवाहों के बयान दर्ज करने तथा नक्शा-नजरी तैयार करने के बाद, विवेचना अधिकारी ने अभियुक्त शेरपाल के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 307 के अंतर्गत आरोप-पत्र प्रस्तुत किया। न्यायालय द्वारा 27.01.2009 को अभियुक्त के विरुद्ध आरोप विरचित किए गए। अभियुक्त-अपीलकर्ता शेरपाल ने आरोपों से इनकार किया और विचारण की मांग किया।

6. अपने मामले को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों का परीक्षण किया: पी.डब्ल्यू.-1 किशनचंद (सूचनादाता), पी.डब्ल्यू.-2 संजीव (मृतका का भाई/चक्षुदर्शी गवाह), पी.डब्ल्यू.-3 कु. अंजू (मृतका की बहन/चक्षुदर्शी गवाह), पी.डब्ल्यू.-4 रमेश चंद (चक्षुदर्शी गवाह), पी.डब्ल्यू.-5 कांस्टेबल 734 देवेंद्र सिंह, पी.डब्ल्यू.-6 उप-निरीक्षक कन्हैयालाल चौधरी, पी.डब्ल्यू.-7 डॉ. बी.पी. सिंह कल्याणी, पी.डब्ल्यू.-8 थानाध्यक्ष बलवीर सिंह।

7. अभियोजन पक्ष ने अवर न्यायालय के समक्ष विभिन्न दस्तावेजी साक्ष्यों पर भी भरोसा किया, जिनमें शामिल हैं: लिखित शिकायत (प्रदर्श क-1), प्रथम सूचना रिपोर्ट (प्रदर्श क-2), जनरल डायरी प्रविष्टि (प्रदर्श क-3), नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-5), सादी और खून से सनी मिट्टी का बरामदगी फर्द (प्रदर्श क-6), एक 12-बोर के खाली कारतूस का बरामदगी फर्द (प्रदर्श क-7), पंचायतनामा (प्रदर्श क-8), चालान नाश (प्रदर्श क-9), शव का फोटो (प्रदर्श क-10), चिट्ठी प्रतिसार निरीक्षक (प्रदर्श क-11), मुख्य चिकित्सा अधिकारी का पत्र (प्रदर्श क-12), नमूना मुहर (प्रदर्श क-13), पोस्टमार्टम रिपोर्ट (प्रदर्श क-14), हथियार बरामदगी का नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-15), और आरोप-पत्र (प्रदर्श क-16)।

8. पी.डब्ल्यू.-1, किशनचंद, जो वाद में सूचनादाता है, ने अपने मुख्य-परीक्षण में कहा कि मृतका, सीमा, उसकी पुत्री थी और लगभग 16 से 17 वर्ष की थी। 28.06.2008 को सीमा अपनी बहन अंजू और छोटे भाई संजीव के साथ चारा काटने खेत में गई थी। यह खेत उसने राम सिंह से पेशगी (अग्रिम पट्टे) पर लिया था और इसमें ज्वार की फसल बोई गई थी। जब बच्चे फसल काट रहे थे, तब सुबह लगभग 11:00 बजे, अभियुक्त शेरपाल दुर्भावनापूर्ण इरादे से सीमा के पास पहुंचा, उसका हाथ पकड़ा और उसे खेत में खींचने लगा। इस पर, तीनों बच्चों ने शोर मचाया, जिससे वीरपाल और रमेश मौके की ओर दौड़े। क्योंकि उनके समय पर पहुंचने से अभियुक्त सीमा के साथ बलात्कार करने के अपने बुरे इरादे को अंजाम नहीं दे सका, इसलिए अभियुक्त ने एक देशी तमंचे से उसके पेट में गोली मार दी। इसके बाद, शेरपाल उत्तर दिशा की ओर भाग गया।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



वीरपाल और रमेश ने उसका पीछा किया। उस समय तक सूचनादाता भी मौके पर पहुंच गया और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन अभियुक्त ने उस पर गोली चला दी, जिससे वह बाल-बाल बच गया। अभियुक्त मौके से भागने में सफल रहा। वीरपाल, रमेश, सूचनादाता और दोनों नाबालिग बच्चों ने घायल सीमा को बुलंदशहर अस्पताल ले जाने की कोशिश की, लेकिन चोटों की गंभीरता के कारण, स्याना बस स्टैंड के पास रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। अस्पताल पहुंचने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। शव को अस्पताल में छोड़कर, वे रिपोर्ट दर्ज कराने गए। सूचनादाता ने हरिनारायण शर्मा को लिखित शिकायत बोलकर लिखवाई, और सामग्री बिल्कुल वैसे ही लिखी गई जैसा कि बताया गया था। इसे उसे पढ़कर सुनाया गया, जिसके बाद उसने अपने हस्ताक्षर किए। रिपोर्ट गवाहों को भी दिखाई और पढ़कर सुनाई गई, जिन्होंने इसकी सत्यता की पुष्टि की। शिकायत को प्रदर्श क-1 के रूप में चिह्नित किया गया। सूचनादाता फिर मामला दर्ज कराने के लिए रिपोर्ट लेकर पुलिस स्टेशन गया। यह रिपोर्ट पुलिस स्टेशन परिसर के बाहर लिखी गई थी।

9. अपनी प्रति-परीक्षा में, पी.डब्ल्यू.-1 ने कहा कि वह अशिक्षित है और उसने हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं की है। उसने गवाही दी कि उसके गांव में पिछले स्थानीय चुनाव (प्रधानी) के कारण तीव्र राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और गुटबाजी (पार्टी-बंदी) मौजूद थी, जहां दो उम्मीदवार, ओमदत्त और राजेंद्र सैनी एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े थे। गवाह और उसके गुट ने सक्रिय रूप से ओमदत्त का समर्थन किया था, जबकि अभियुक्त शेरपाल ने राजेंद्र सैनी के लिए प्रचार किया था, जिसने उनके बीच गहरी दुश्मनी की नींव रखी। उसने गवाही दी कि अपराध स्थल उसके आवासीय घर से लगभग आधा किलोमीटर दूर स्थित है। अपराध स्थल की स्थलाकृति के संबंध में, गवाह ने कहा कि उसने राम सिंह से 3,000/- रुपये प्रति बीघा की दर से 4-बीघा भूमि किराए पर ली थी, जहां ज्वार की फसल बोई गई थी। उसने खेत की सीमाओं का विवरण दिया, यह बताते हुए कि इसके उत्तर, दक्षिण और पूर्व में राम सिंह की अन्य भूमि थी, जबकि पश्चिम में एक पानी की नाली, एक चकरोड और मवासी का खेत था। उसने आगे बताया कि रमेश (मल्ही का पुत्र) का खेत और दक्षिण में था, जो केवल कछीद बक्शा के खेत से अलग था, और राम सिंह की कुल चकबंदी वाली जोत लगभग 48 से 50 बीघा थी।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



10. गवाह ने आगे कहा कि मनहूस दिन, सुबह लगभग 10:30 से 10:45 बजे के बीच, उसके परिवार के सदस्य खड़ी ज्वार की फसल काटने के लिए घर से निकले थे, जो लगभग 6 से 7 फीट ऊंची थी लेकिन विरल (दूर-दूर) बोई गई थी। उस समय चारों दिशाओं में आसपास के खेत खाली थे। गवाह लगभग 4 से 6 मिनट के अंतराल के बाद बच्चों के पीछे-पीछे गया। जब वह लगभग एक खेत की दूरी पर था, तो उसने तेज शोर सुना और उस स्थान की ओर दौड़ा। लगभग 25 से 30 मीटर की दूरी से, उसने सीधे हमलावर को पीड़िता पर गोली चलाते हुए देखा, जो उसके पेट में लगी। यह देखकर गवाह और अन्य लोगों ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया। भागने में सुविधा के लिए, अभियुक्त मुड़ा और 40 से 45 मीटर की दूरी से पीछा करने वालों पर सीधे गोली चलाई, जो बाल-बाल बची। अभियुक्त के भागने में सफल होने से पहले पीछा लगभग 15 से 20 मिनट तक चला।

11. पी.डब्ल्यू.-1 ने बाद की घटनाओं का वर्णन करते हुए कहा कि गोली चलने के बाद वे लगभग 20 मिनट तक खेत में रहे, फिर घायल लड़की को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए घोड़ा-गाड़ी (बोगी) में लादा। कटाई के औजार जिनमें तीन दरांती और रस्सियों के साथ कटी हुई फसल शामिल थी, वहीं मौके पर छोड़ दिए गए। वे लगभग 11:45 बजे पुलिस स्टेशन पहुंचे, और वहां 7 से 8 मिनट बिताने के बाद, लिखित शिकायत (तहरीर) औपचारिक रूप से दोपहर 12:00 बजे सौंप दी गई। यह शिकायत पुलिस स्टेशन के बाहर ग्राम मूढ़ी बकापुर के हरिनारायण द्वारा लिखी गई थी, जिसे गवाह जानता था और साथ लाया था। गवाह ने कहा कि जब उसने पीड़िता को बगगी में उठाया तो उसके खुद के कपड़े खून से बहुत ज्यादा सन गए थे, जिसे उसने बाद में विवेचना अधिकारी को सौंप दिया था। उसने यह भी बताया कि मृतका ने गले में चांदी की जंजीर (चेन) पहनी हुई थी। पुलिस स्टेशन से अस्पताल ले जाते समय, घायल लड़की ने स्याना बस स्टैंड के पास दम तोड़ दिया और दोपहर 12:15 बजे अस्पताल पहुंचने पर उसे आधिकारिक तौर पर मृत लाया गया, घोषित कर दिया गया।

12. गवाह ने आगे गवाही दी कि पुलिस उसी दिन दोपहर बाद 3:00 बजे से 4:00 बजे के बीच गांव पहुंची, और उसी दिन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत उसका बयान दर्ज किया। अन्य ग्रामीण, रमेश और वीरपाल भी मौके पर पहुंचे, वीरपाल की भूमि घटना स्थल के ठीक दक्षिण में स्थित थी। पंचायतनामा की कार्यवाही उसकी उपस्थिति में अस्पताल में पोस्टमार्टम से

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लगभग एक घंटे पहले की गई थी, और पोस्टमार्टम परीक्षण लगभग 3:00 बजे किया गया था। बाद में शाम 4:00 बजे से 4:30 बजे के बीच शव परिवार को सौंप दिया गया।

13. अपनी प्रति-परीक्षा में, पी.डब्ल्यू.-1 का सामना कई बचाव सिद्धांतों और प्रारंभिक दस्तावेजीकरण में चूक से हुआ। उसने जोर देकर कहा कि अभियुक्त हल्का सा लंगड़ा कर चलने के बावजूद बहुत तेज दौड़ता है, और उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया कि अभियुक्त के दाहिने पैर में पोलियो था। जब लिखित शिकायत में विशेष रूप से भूमि पट्टे के विवरण, पीड़िता को किस सटीक स्थान पर घसीटा गया, खेत के स्वामित्व, पीछा करने के दौरान जवाबी गोलीबारी के सटीक बिंदु और इस्तेमाल किए गए वाहन के उल्लेख के संबंध में चूक का सामना करना पड़ा, तो गवाह ने कहा कि उसने इन तथ्यों को विवेचना अधिकारी को बताया था और औपचारिक पाठ से उनके छूटने का कोई कारण नहीं बता सकता। अंततः, गवाह ने बचाव पक्ष के सुझावों का दृढ़ता से खंडन किया कि उसने एक झूठा मामला गढ़ा था क्योंकि उस पर अभियुक्त शेरपाल का 50,000/- रुपये का कर्ज था, या कि वह गांव की गुटबाजी के कारण झूठी गवाही दे रहा था। उसने इस बात से इनकार किया कि केवल सत्यवीर और सीताराम पुलिस स्टेशन गए थे, कि मृतका को कभी अस्पताल नहीं ले जाया गया था, या कि मूल शिकायत को मनगढ़ंत शिकायत से बदल दिया गया था, और यह कायम रखा कि उसका विवरण पूरी तरह से सत्य था।

14. अभियोजन पक्ष ने आगे पी.डब्ल्यू.-2, संजीव कुमार, पुत्र किशन चंद, उम्र लगभग 12 वर्ष, कक्षा 6 का छात्र, और मुनी बकापुर, औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर के निवासी का परीक्षण किया। इस गवाह ने शपथ की पवित्रता की समझ रखते हुए कहा कि मृतका, सीमा, उसकी बड़ी बहन थी और वह अभियुक्त शेरपाल को पहचानता था, जो उसके गांव का था। पी.डब्ल्यू.-2 ने गवाही दी कि घटना 28 जून, 2008 को सुबह लगभग 11:00 बजे हुई जब वह अपनी बहनों सीमा और अंजू के साथ उस खेत में ज्वार काट रहा था जिसे उसके परिवार ने किराए (पेशगी) पर लिया था। उसने गवाही दी कि अभियुक्त शेरपाल खाली खेतों से मौके पर पहुंचा, उसकी बहन सीमा का हाथ पकड़ा, और उसे जबरन ज्वार के खेत में खींचने लगा। जब गवाह ने अपनी बहन अंजू के साथ विरोध किया और शोर मचाया, तो शोर से आकर्षित होकर वीरपाल और रमेश सहित कई ग्रामीण मौके की ओर दौड़े। इस पर, अभियुक्त शेरपाल ने अपनी कमर (आंटी) से एक देशी तमंचा निकाला

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और उसकी बहन सीमा पर सीधा फायर कर दिया, जिससे उसके पेट में गोली लग गई। गवाह ने आगे कहा कि जब उन्होंने हमलावर को पकड़ने का प्रयास किया, तो अभियुक्त ने मुड़कर उन पर फायर किया, लेकिन वे बाल-बाल बच गए, जिससे अभियुक्त को मौके से भागने का मौका मिल गया। पी.डब्ल्यू.-2 ने तुरंत अपने पिता और अन्य ग्रामीणों को घटना का विवरण सुनाया, और कहा कि जब उसके परिवार के सदस्य सीमा को अस्पताल ले जा रहे थे, तो रास्ते में ही उसकी चोटों से मृत्यु हो गई। उसने आगे उल्लेख किया कि इस घटना से पूर्व, अभियुक्त ने सीमा को परेशान किया था और उसके साथ दुर्व्यवहार किया था, जिसके कारण एक ग्राम पंचायत हुई थी जहां अभियुक्त शेरपाल ने माफी मांगी थी।

15. आगे के परीक्षण के लिए वापस बुलाए जाने पर, पी.डब्ल्यू.-2 ने गवाही दी कि घटना के दिन, वे सुबह लगभग 11:00 बजे अपने घर से निकले थे और लगभग आधे घंटे बाद खेत में पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वार की लगभग 2 से 3 गड़्डी काटी, जिस काम में लगभग एक घंटा लगा। उसने दोहराया कि प्रश्नगत खेत राम सिंह के खेत के उत्तर में स्थित था और कई अन्य कृषि भूखंडों से घिरा हुआ था, हालांकि वह सभी आस-पास की जमीनों के स्वामित्व को निर्दिष्ट नहीं कर सका। पी.डब्ल्यू.-2 ने स्पष्ट किया कि मौके पर एक ही गोली चलाई गई थी, और गोली चलने के बाद, वे कटी हुई फसल, रस्सियां और दरांती पीछे छोड़कर खेत से भाग गए। उसने कहा कि उसके पिता घटना के तुरंत बाद, लगभग 20 मिनट के भीतर मौके पर पहुंचे, हालांकि गोलीबारी उसके पिता की उपस्थिति में नहीं हुई थी। उसने कहा कि ग्रामीण शुरु में सीमा को अस्पताल की ओर ले गए और उसकी मृत्यु की सूचना उसके निधन के बाद ही मिली, जिसके बाद उसके पिता और अन्य लोग अस्पताल गए। अभियुक्त की शारीरिक स्थिति के संबंध में बचाव पक्ष के सुझावों का सामना करने पर, गवाह ने कहा कि अभियुक्त अपने दाहिने पैर में लंगड़ा कर चलता है, लेकिन इस दावे से इनकार किया कि अभियुक्त दौड़ नहीं सकता। पी.डब्ल्यू.-2 ने आगे कहा कि घटना से लगभग 15 दिन पहले, उसने व्यक्तिगत रूप से अभियुक्त को एक अज्ञात व्यक्ति के साथ अपनी बहन सीमा को परेशान करते हुए देखा था, जिसके कारण लगभग 20 दिन बाद ग्राम पंचायत हुई, हालांकि उसने स्वीकार किया कि वह व्यक्तिगत रूप से पंचायत बैठक में शामिल नहीं हुआ था। गवाह ने बचाव पक्ष के इन सिद्धांतों से इनकार किया कि अभियुक्त ने कोई उत्पीड़न नहीं किया था, कि ऐसी कोई पंचायत नहीं हुई थी, या कि वे राम सिंह के खेत के दक्षिणी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



तरफ ज्वार काट रहे थे। उसने आगे उन सुझावों का खंडन किया कि वह गांव की गुटबाजी के कारण झूठी गवाही दे रहा था, कि पूरी घटना मनगढ़ंत थी, या कि एक फर्जी डकैती के बहाने अभियुक्त के खिलाफ झूठा मामला दर्ज किया गया था।

16. अभियोजन पक्ष ने पी.डब्ल्यू.-3, कुमारी अंजू, पुत्री किशन चंद, उम्र लगभग 14 वर्ष, जो कक्षा 4 तक पढ़ी है और मूढ़ी बकापुर, औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर में रहती है, को भी प्रस्तुत किया। पी.डब्ल्यू.-3 ने गवाही दी कि मृतका, सीमा, उसकी बड़ी बहन थी। उसने कहा कि उसकी गवाही से लगभग एक साल और दो महीने पहले, वह अपनी बड़ी बहन सीमा और अपने भाई संजीव के साथ राम सिंह के खेत में चारा काटने गई थी, जिसे उनके परिवार ने किराए पर लिया था। सुबह लगभग 11:00 बजे, जब वे तीनों फसल काट रहे थे, अभियुक्त शेरपाल खाली खेतों से निकला, सीमा का हाथ पकड़ा और जबरन उसे ज्वार के खेत में खींचने की कोशिश की। सीमा ने विरोध किया, और जब गवाह ने संजीव के साथ जोर से शोर मचाया, तो गांव के स्थानीय लोग रमेश और वीरपाल मौके की ओर दौड़े। उसी क्षण, अभियुक्त शेरपाल ने अपनी कमर (आंटी) से एक देशी तमंचा निकाला और उसकी बहन सीमा के पेट में गोली मार दी। पी.डब्ल्यू.-3 ने गवाही दी कि, जब एकत्र हुए ग्रामीणों ने अभियुक्त को पकड़ने का प्रयास किया, तो उसने अपने भागने को सुरक्षित करने के लिए अपने हथियार से उन पर गोलियां चलाईं। घायल सीमा को बाद में ग्रामीणों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में ही उसका निधन हो गया।

17. आगे की प्रति-परीक्षा के लिए वापस बुलाए जाने पर, पी.डब्ल्यू.-3 ने कहा कि घटना के दिन मौसम बारिश का था और खड़ी ज्वार की फसल लगभग 6 से 7 फीट ऊंची थी। उसने स्पष्ट किया कि वे अपना भोजन करने के बाद सुबह लगभग 11:00 बजे अपने घर से निकले थे, कृषि भूखंड तक पहुंचने में लगभग आधा घंटा लगा था, और ज्वार की एक गड़्डी काटने में और आधा घंटा बिताया था। गवाह ने जोर देकर कहा कि वह दिशाओं को समझती है और वर्णन किया कि ज्वार राम सिंह की भूमि के दक्षिण में चकरोड वाले हिस्से में बोया गया था। उसने कहा कि, जब वे खेत के दक्षिण-पूर्व कोने के पास फसल काट रहे थे, एक व्यक्ति उत्तर दिशा से आया, सीमा को पकड़ा और उसे गोली मार दी। हमले के बाद, वे डर के मारे खेत से भाग गए, रस्सियां, दरांती और कटी हुई फसल वहीं छोड़ गए। घायल पीड़िता को ग्रामीणों द्वारा अस्पताल ले जाया गया, और उसकी मृत्यु की खबर मिलने पर, उसके पिता और परिवार के अन्य सदस्य अस्पताल गए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



पी.डब्ल्यू.-3 ने बचाव पक्ष के सुझावों को दृढ़ता से खारिज कर दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई थी, कि तथ्यों का उसका विवरण झूठा था, या कि उसने अपराध को होते हुए नहीं देखा था।

18. अभियोजन पक्ष ने आगे पी.डब्ल्यू.-4, रमेश चंद, पुत्र मल्ली सिंह, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी मूढ़ी बकापुर, पुलिस स्टेशन औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर का परीक्षण किया। गवाह ने शपथ पर गवाही दी कि घटना लगभग 16 महीने पहले सुबह करीब 11:00 बजे हुई थी। उसने कहा कि वह अपने खेत पर काम कर रहा था और मेड़ पर बैठकर वीरपाल के साथ बीड़ी पी रहा था जब उन्होंने अचानक तेज शोर सुना। जांच करने के लिए खड़े होने पर, उन्होंने देखा कि अभियुक्त शेरपाल स्पष्ट अवैध इरादे से पीड़िता सीमा को उसकी बांह से जबरन खींच रहा है, उसे खड़ी ज्वार की फसल में खींच रहा है। पी.डब्ल्यू.-4 ने गवाही दी कि, जब वे सीमा के चीखने पर मौके की ओर बढ़े, तो अभियुक्त ने उनके आने पर ध्यान दिया और तुरंत पीड़िता के पेट में सीधे गोली मार दी। गवाह और वीरपाल ने भागते हुए हमलावर का पीछा किया, लेकिन अभियुक्त मुड़ा और उन पर गोली चला दी, जिससे उन्हें अपनी जान बचाने के लिए रुकना पड़ा, जिसके बाद अभियुक्त उत्तर दिशा की ओर भाग गया। अपराध स्थल के पास पहुंचने पर, पी.डब्ल्यू.-4 ने पाया कि दो से चार अन्य ग्रामीण मौके पर जमा हो रहे थे, जिसके कुछ ही देर बाद पीड़िता के पिता किशन चंद भी वहां पहुंच गए। घायल लड़की को बाद में एक घोड़ा-गाड़ी (बग्गी) में रखा गया जो जंगल क्षेत्र में खड़ी थी, गांव ले जाया गया, और फिर चिकित्सा सहायता के लिए बुलंदशहर ले जाने के लिए तुरंत एक मोटर कार में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि गवाह गांव में ही पीछे रह गया।

19. प्रति-परीक्षा के दौरान, पी.डब्ल्यू.-4 ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त ने भागते समय लगभग 50 कदम की दूरी से उस पर हथियार चलाया था, और भागने के दौरान बार-बार पीछे मुड़कर देख रहा था। उसने कहा कि जिस मेड़ पर वह और वीरपाल बैठे थे, वह ज्वार के खेत से लगभग 40 से 50 मीटर दूर स्थित थी, जहां बच्चे कटाई कर रहे थे। उसने कहा कि प्रश्नगत खेत किशन चंद का था, जिसने राम सिंह की 50 बीघा की कुल जोत में से 4 से 5 बीघा पट्टे पर लिया था। स्थानीय सीमाओं के संबंध में, उसने वर्णन किया कि नौरंग का खेत पूर्व में, नरेश, महीचंद और अमरपाल के खेत पश्चिम में, और वीरपाल का खेत दक्षिण में था। पी.डब्ल्यू.-4 ने निर्दिष्ट किया कि उसकी खुद की 10 बीघा की जोत वीरपाल के 20 से 21 बीघा के ठीक बाईं ओर थी। उसने

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



आगे कहा कि वे खाली हाथ मौके की ओर दौड़े, अपने कृषि उपकरण (खुरपी और फावड़ा) पीछे छोड़ गए। उसने पुष्टि की कि अपराध स्थल पर दो गोलियां चलाई गईं और वर्णन किया कि हमले से पहले ज्वार की लगभग 1 से 2 कतारें काटी गई थीं, जिसमें कटी हुई गड़्डियां और दो दरांती जमीन पर छोड़ी गई थीं, हालांकि कोई रस्सियां मौजूद नहीं थीं। उसने देखा कि पीड़िता ने उस समय पीले रंग का सूट पहना हुआ था, लेकिन लॉकेट जैसे किसी विशिष्ट आभूषण को याद नहीं कर सका। पी.डब्ल्यू.-4 ने स्थानीय राजनीतिक गुटबाजी से संबंधित बचाव सिद्धांतों को खारिज कर दिया, यह देखते हुए कि, हालांकि वह सूचनादाता की तरह लोध राजपूत समुदाय से है, वह उससे संबंधित नहीं है। उसने गांव के चुनावों में ओमदत्त को वोट देने की बात स्वीकार की, जबकि राजेंद्र सैनी प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवार थे, लेकिन इस बात से दृढ़ता से इनकार किया कि गांव की राजनीति ने पुरानी दुश्मनी पैदा की है या झूठे फंसाने का कारण बनी है। उसने बचाव पक्ष के दावों का दृढ़ता से खंडन किया कि उसने घटना को नहीं देखा, कि पीड़िता किसी अज्ञात हमलावर द्वारा मारी गई थी, या कि डकैती के झूठे आरोप को छिपाने के लिए अभियुक्त के खिलाफ एक मनगढ़ंत मामला बनाया गया था।

20. अभियोजन पक्ष ने आगे पी.डब्ल्यू.-5, कांस्टेबल देवेंद्र सिंह का परीक्षण किया, जिसने गवाही दी कि 28 जून 2008 को वह पुलिस स्टेशन औरंगाबाद में तैनात था। उसने गवाही दी कि सूचनादाता किशन चंद द्वारा प्रस्तुत लिखित शिकायत (तहरीर) के आधार पर, उसने अपराध संख्या 176/08 के अंतर्गत औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) दर्ज किया। मूल चिक एफ.आई.आर., जो उसकी अपनी लिखावट में लिखी गई थी और जिस पर उसके हस्ताक्षर थे, औपचारिक रूप से न्यायालय के समक्ष प्रदर्श क-2 के रूप में प्रदर्शित की गई थी। पी.डब्ल्यू.-5 ने आगे कहा कि उसने उसी दिन दोपहर 2:45 बजे रपट संख्या 171 के रूप में जनरल डायरी (जी.डी.) में संबंधित प्रविष्टि दर्ज की। वह मूल जनरल डायरी को न्यायालय में लाया और सत्यापित किया कि मामले की पत्रावली में निहित कार्बन कॉपी मूल रजिस्टर के समान ही प्रक्रिया में तैयार की गई थी, और प्रविष्टि को प्रदर्श क-3 के रूप में चिह्नित किया गया था।

21. अपनी प्रति-परीक्षा के दौरान, पी.डब्ल्यू.-5 ने स्वीकार किया कि दस्तावेज़ के कॉलम 15 में दिनांक और समय के संबंध में एक चूक थी। उसने जोर देकर कहा कि उस दिन वर्तमान मामले को दर्ज करने से पहले या बाद में स्टेशन पर कोई अन्य आपराधिक वाद दर्ज नहीं किया गया

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



था। उसने बचाव पक्ष के इस सुझाव का कड़ाई से खंडन किया कि एफ.आई.आर. सूचनादाता की मिलीभगत से पिछली तारीख डालकर "एंटी-टाइम" (समय-पूर्व) दस्तावेज़ के रूप में दर्ज की गई थी। उसने इंगित किया कि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सी.जे.एम.) की 4 जुलाई 2008 की मुहर प्रदर्श क-2 के ठीक नीचे लगी हुई थी, और ध्यान दिया कि, यद्यपि क्षेत्राधिकारी (सी.ओ.) ने दस्तावेज़ पर हस्ताक्षर किए थे, उस विशेष हस्ताक्षर के नीचे कोई तिथि निर्दिष्ट नहीं थी।

22. अभियोजन पक्ष ने आगे पी.डब्ल्यू.-6, उप-निरीक्षक के.एल. चौधरी, जो मामले के प्रथम विवेचना अधिकारी थे और तत्कालीन थानाध्यक्ष (एस.ओ.) पुलिस स्टेशन औरंगाबाद थे, का परीक्षण किया। उन्होंने गवाही दी कि 28 जून 2008 को उन्होंने भारतीय दंड संहिता (आई.पी.सी.) की धारा 302 और 307 के अंतर्गत पंजीकृत अपराध संख्या 176/08 की विवेचना का कार्यभार संभाला। उसी दिन, उन्होंने सूचनादाता किशन चंद, एफ.आई.आर. के लेखक और चक्षुदर्शी गवाह संजीव कुमार के बयान दर्ज किए। उन्होंने बाद में घटना स्थल का निरीक्षण किया और अपनी लिखावट में नक्शा-नजरी तैयार किया, जिसे प्रदर्श क-5 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। गवाह ने गवाही दी कि घटना की तिथि पर, उसने मौके से सादी मिट्टी के साथ खून से सनी मिट्टी के नमूने एकत्र किए और मौके के गवाहों की उपस्थिति में एक बरामदगी ज़ापन (फर्द) तैयार किया, जिसे प्रदर्श क-6 के रूप में चिह्नित किया गया था। उसने अपराध स्थल से एक 12-बोर का खाली कारतूस का खोखा भी बरामद किया, जिसे गवाहों की उपस्थिति में एक औपचारिक मुहर और ज़ापन के तहत एक कपड़े के डिब्बे (कंटेनर) में सील कर दिया गया था।

23. न्यायालय की कार्यवाही के दौरान, न्यायालय के भंडार कक्ष से प्राप्त एक सीलबंद बंडल गवाह के समक्ष खोला गया, जिसमें टी.सी.-1, टी.सी.-2 और टी.सी.-3 चिह्नित तीन खाली कारतूस के खोखे, एक जिंदा कारतूस के साथ दिखाई दिए। पी.डब्ल्यू.-6 ने इन वस्तुओं को फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए गोला-बारूद के रूप में पहचाना, और उन्हें भौतिक प्रदर्श 1 और 9 के रूप में चिह्नित किया गया। एक दूसरा सीलबंद बंडल खोला गया, जिससे गवाह ने स्पष्ट रूप से उस विशिष्ट खाली कारतूस के खोखे की पहचान की जिसे उसने मौके से बरामद किया था, जिसे भौतिक प्रदर्श 5 के रूप में चिह्नित किया गया था। उन्होंने आगे गवाही दी कि 29 जून 2008 को उन्होंने गांव के बाजार (कटरा) में गवाह करण सिंह और सुरेश के बयान दर्ज किए, मृतका सीमा की पंचायतनामा और पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्राप्त की, और उन्हें केस डायरी (सी.डी.) में

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



लिप्यंतरित किया। उन्होंने स्टेशन से अपने बाद के स्थानांतरण से पहले कांस्टेबल सुभाष बाबू और सहदेव के बयान भी दर्ज किए। पी.डब्ल्यू.-6 ने आगे कहा कि मृतका सीमा की पंचायतनामा कार्यवाही 28 जून 2008 को उनके निर्देशों के तहत उप-निरीक्षक एस.पी. सिंह द्वारा की गई थी। मूल पंचायतनामा रिपोर्ट, जिस पर एस.पी. सिंह के हस्ताक्षर और पंच गवाहों के हस्ताक्षर थे, को प्रदर्श क-8 के रूप में प्रदर्शित किया गया था। उन्होंने सत्यापित किया कि उसी दिन, एस.आई. एस.पी. सिंह ने आवश्यक अग्रेषण कागजी कार्रवाई तैयार की, जिसमें शव का पुलिस चालान (चालान नाश), नमूना मुहर के लिए प्रपत्र, शव का फोटो और प्रतिसार निरीक्षक (आर.आई.) तथा मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सी.एम.ओ.) को संबोधित औपचारिक पत्र शामिल हैं, जिन्हें प्रदर्श क-9 से क-13 के रूप में प्रदर्शित किया गया था।

24. जब प्रति-परीक्षा की गई, तो पी.डब्ल्यू.-6 ने कहा कि वह 11 महीने से पुलिस स्टेशन औरंगाबाद में तैनात थे, हालांकि वह अपने कार्यकाल की सटीक तिथियां याद नहीं कर सके। उन्होंने स्वीकार किया कि बरामदगी ज्ञापन प्रदर्श क-5 में स्पष्ट रूप से मौके पर किसी कटी हुई ज्वार, दरांती या रस्सियों को नहीं दर्शाया गया है, न ही इसमें मौके पर गवाहों के प्रवेश या निकास के सटीक मार्गों को चिह्नित किया गया है। उन्हें गवाहों के धारा 161 सीआरपीसी के बयानों में चूक का सामना करना पड़ा; उन्होंने ध्यान दिया कि सूचनादाता किशन चंद ने अपनी प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह नहीं बताया था कि उसने अभियुक्त का पीछा किया था या अभियुक्त ने उस पर वापस गोली चलाई थी। उन्होंने आगे ध्यान दिया कि किशन चंद ने जांच के उनके हिस्से के दौरान उन्हें कोई खून से सने कपड़े नहीं सौंपे थे। उन्होंने पुष्टि की कि बाल गवाह संजीव कुमार ने अपने प्रारंभिक बयान में यह नहीं कहा था कि उसके पिता "10 मिनट के बाद या कुछ ही समय में" मौके पर पहुंचे, और कुमारी अंजू का यह बयान कि जब ग्रामीणों ने उसे पकड़ने की कोशिश की तो अभियुक्त ने हथियार चलाया था, केस डायरी से गायब था।

25. पी.डब्ल्यू.-6 ने स्पष्ट किया कि ये चूक बाद के विवेचना अधिकारी द्वारा दर्ज की जा सकती हैं जिसने मामला संभाला था। उन्होंने कहा कि उन्होंने तुलना के लिए फॉरेंसिक लैब में बरामद कारतूस के खोखों को व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजा था, क्योंकि यह प्रक्रिया दूसरे विवेचना अधिकारी द्वारा की गई थी, और वह उन कारतूसों की पहचान संख्या निर्दिष्ट नहीं कर सके। उन्होंने सत्यापित किया कि खाली कारतूस वाले बंडल पर उनके हस्ताक्षर मौजूद थे। अंततः, जब

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



प्रक्रियात्मक विवरणों के बारे में पूछताछ की गई, तो उन्होंने ध्यान दिया कि शेष कपड़े फटे हुए थे, प्रदर्श क-8 पर उनके हस्ताक्षर नहीं थे, और पंचायतनामा रिपोर्ट में स्पष्ट रूप से यह उल्लेख नहीं किया गया था कि यह उनके सीधे निर्देशों के तहत तैयार की गई थी या इसमें अभियुक्त का नाम, मुकदमा अपराध संख्या या वैधानिक धाराएं शामिल थीं। उन्होंने बचाव पक्ष के इन सुझावों का कड़ाई से खंडन किया कि उन्होंने कभी मौके का दौरा नहीं किया, कि उनके द्वारा कोई खाली कारतूस बरामद नहीं किया गया था, या कि पूरी विवेचना पुलिस स्टेशन में बैठकर की गई थी।

26. अभियोजन पक्ष ने आगे पी.डब्ल्यू.-7, डॉ. वी.पी. सिंह कल्याणी का परीक्षण किया, जिन्होंने कहा कि 28.06.2008 को वह जिला अस्पताल, बुलंदशहर में चिकित्सा अधिकारी के रूप में तैनात थे। उस दिन, शाम 4:50 बजे, उन्होंने मूढ़ी बकापुर, पुलिस स्टेशन औरंगाबाद, जिला बुलंदशहर निवासी किशन चंद की पुत्री कुमारी सीमा के शव का पोस्टमार्टम परीक्षण किया। शव को थानाध्यक्ष (एस.एच.ओ.), औरंगाबाद द्वारा एक कपड़े में सील करके, संबंधित पुलिस कागजातों के साथ भेजा गया था। कांस्टेबल 962 सुभाष बाबू और सी.पी. 150 सहदेव सिंह, जो शव को स्टेशन लाए थे, ने इसकी पहचान की। शव पर लगी मुहर के नमूने का मिलान नमूना मुहर से किया गया और वह अक्षुण्ण पाया गया। मृतका की आयु लगभग 17 वर्ष थी और उसकी मृत्यु हुए लगभग एक चौथाई दिन हो चुका था। वह सामान्य कद-काठी की थी। उसके शरीर के ऊपरी हिस्से में अकड़न विकसित हो रही थी। उसके दोनों हाथ और पैर कीचड़ से सने हुए थे।

27. मृतका के शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई गईं: प्रवेश का स्थान 1.5 सेमी x 1.00 सेमी था, जो पेट की गुहा में गहराई तक फैला हुआ था, जो पेट के दाहिने हिस्से में, नाभि से 1 सेमी की दूरी पर 7 बजे की स्थिति में स्थित था। घाव के किनारे उल्टे थे, और किनारों के साथ कालापन और गुदना था। घाव से आंते बाहर निकली हुई थीं। विच्छेदन करने पर, पेरिटोनियम, बाईं किडनी और तिल्ली फटी हुई पाई गई। पेट से एक प्लास्टिक की अंगूठी (रिंग) और 15 छर्रे (धातु के टुकड़े) बरामद किए गए। पेट की गुहा में लगभग 1200 मिलीलीटर रक्त मौजूद था। सभी आंतरिक अंग पीले/पीत दिखाई दे रहे थे। मृतका के पेट में 150 ग्राम बिना पचा हुआ भोजन था, और उसका पित्ताशय आंशिक रूप से भरा हुआ था। मृतका के अंडाशय साफ थे। मृतका ने कुर्ता, कमीज, सलवार, दो दुपट्टे, एक अंगूठी, सफेद धातु के दो छल्ले, एक हेयर बैंड, दो झुमके, एक सफेद धातु की जंजीर (चेन), एक नोज पिन और कांच की चूड़ी के टुकड़े पहने हुए थे, इन सभी को एक

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



कपड़े में सील कर दिया गया था। पेट से निकाली गई टिकली और 15 धातु के टुकड़ों को एक सीलबंद लिफाफे में रखकर साथ आए पुलिस कर्मियों को सौंप दिया गया। पुलिस के कागजात, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और शव भी उन्हें सौंप दिए गए। उनकी राय में, मृतका की मृत्यु मृत्यु-पूर्व चोटों के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव से हुई। दिनांक 27.01.2010 की मूल पोस्टमार्टम रिपोर्ट को अभिलेख पर सत्यापित किया गया और प्रदर्शक-14 के रूप में चिह्नित किया गया। डॉक्टर ने राय दी कि, मृतका को 28.06.2008 को सुबह लगभग 11:00 बजे चोटें लगना पूरी तरह से संभव था।

28. बचाव पक्ष के वकील द्वारा प्रति-परीक्षा करने पर, गवाह ने कहा कि मृतका ने अपनी मृत्यु से 2 से 3 घंटे पहले भोजन किया होगा। उन्होंने स्वीकार किया कि यह संभव है कि 28.06.2008 को सुबह लगभग 10:00 बजे मृतका की मृत्यु हुई हो, यह देखते हुए कि मृत्यु का समय 1 से 1.5 घंटे तक भिन्न हो सकता है। उन्होंने ध्यान दिया कि जिस सतह पर मृतका गिरी वह कीचड़दार रही होगी। उन्होंने कहा कि वह उस व्यक्ति की सटीक स्थिति को निर्णायक रूप से निर्धारित नहीं कर सकते जिसने मृतका को गोली मारी थी, चाहे वे सीधे उसके सामने खड़े हों या कहीं और। उन्होंने आगे कहा कि वह उस सटीक दूरी को निर्धारित नहीं कर सकते जहां से चोट पहुंचाई गई थी, या क्या यह 10 से 12 फीट की दूरी से थी।

29. अभियुक्त का बयान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के अंतर्गत दर्ज किया गया था, जिसमें उसने कहा कि पूरी अभियोजन कहानी झूठी, निराधार, गढ़ी हुई और मनगढ़ंत है, और गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य गलत हैं। अभियुक्त ने आगे कहा कि उसे वर्तमान वाद में झूठा फंसाया गया है, कि उसने अभियोजन पक्ष द्वारा आरोपित कोई अपराध नहीं किया है, और यह कि प्रथम सूचना रिपोर्ट गुप्त उद्देश्य से दर्ज की गई थी। अभियुक्त-अपीलकर्ता शेरपाल ने यह भी तर्क दिया कि उसने अपनी बेटी की शादी संपन्न करने के लिए सूचनादाता किशनचंद को 50,000/- रुपये दिए थे, और उसी उद्देश्य के लिए सूचनादाता को पहले 10,000/- रुपये दिए थे। उसने आरोप लगाया कि क्योंकि सूचनादाता पैसे वापस नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने अभियुक्त को झूठा फंसाया। इसके अलावा, अभियुक्त शेरपाल ने कहा कि वह एक पैर से दिव्यांग है और इसलिए अपराध नहीं कर सकता था और तुरंत मौके से भाग नहीं सकता था, जिससे यह प्रदर्शित होता है कि पूरी अभियोजन कहानी झूठी है।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



30. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि पूरी अभियोजन कहानी गहरी जड़ें जमा चुकी गांव की राजनीतिक गुटबाजी और वित्तीय दुश्मनी के ताने-बाने से बुनी गई है। यह प्रस्तुत किया गया था कि लिखित शिकायत (प्रदर्श क-1) और सीआरपीसी की धारा 161 के अंतर्गत दर्ज प्रारंभिक बयानों में महत्वपूर्ण चूक, विशेष रूप से पीछा करने के संबंध में चूक, अभियुक्त द्वारा कथित जवाबी गोलीबारी, और नक्शा-नजरी (प्रदर्श क-5) में किसी कटी हुई फसल, दरांती या रस्सियों की अनुपस्थिति चक्षुदर्शी गवाहों के विवरण की विश्वसनीयता को गंभीर रूप से कमजोर करती है।

31. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलकर्ता की शारीरिक विकलांगता, जो अपने दाहिने पैर में स्पष्ट लंगड़ाहट से पीड़ित है, अभियोजन पक्ष के इस दावे को पूरी तरह से गलत साबित करती है कि उसने मृतका को घसीटा और बाद में 20 मिनट के पीछा करने के दौरान फुर्तीले लोगों के एक समूह को पीछे छोड़ दिया। पी.डब्ल्यू.-7 की चिकित्सीय गवाही की ओर इशारा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि मृत्यु के अनुमानित समय में भिन्नता और बिना पचे भोजन की उपस्थिति यह सुझाव देती है कि घटना बहुत पहले एकांत में हुई थी, और अपीलकर्ता को बाद में 60,000/- रुपये के बकाया ऋण से बचने के लिए सूचनादाता के इशारे पर फंसाया गया था।

32. इसके विपरीत, राज्य-प्रत्यर्थी के लिए विद्वान ए.जी.ए.-प्रथम ने आक्षेपित निर्णय का दृढ़ता से बचाव किया और तर्क दिया कि अभियोजन का मामला तीन सुसंगत चक्षुदर्शी गवाहों की गवाही की अटूट नींव पर खड़ा है, जिसमें दो स्वाभाविक बाल गवाह (पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3) शामिल हैं जो अपनी मृत बहन के साथ अपराध स्थल पर मौजूद थे। विद्वान ए.जी.ए. ने प्रस्तुत किया कि प्रारंभिक दस्तावेजीकरण में मामूली भिन्नताएं या चूक क्रूर हमले के ज्वलंत, सुसंगत और मौखिक विवरणों को नजरअंदाज नहीं कर सकती हैं।

33. विद्वान ए.जी.ए. द्वारा यह भी तर्क दिया गया कि चिकित्सा साक्ष्य निर्बाध रूप से मौखिक गवाही की पुष्टि करता है, क्योंकि घाव के उल्टे किनारे, कालापन और गुदना निर्णायक रूप से अभियोजन पक्ष द्वारा बताए गए समय पर निकट दूरी से लगी आग्नेयास्त्र की चोट को स्थापित करते हैं। विद्वान ए.जी.ए. ने निष्कर्ष निकाला कि शारीरिक विकलांगता का बचाव केवल एक बहाना था, क्योंकि लंगड़ा कर चलने से कोई व्यक्ति ट्रिगर खींचने में असमर्थ नहीं हो जाता है,

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



और एफ.आई.आर. का तुरंत दर्ज होना जानबूझकर मनगढ़ंत कहानी बनाने या झूठा फंसाने की किसी भी संभावना को पूरी तरह से खारिज करता है।

34. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि बाल चक्षुदर्शी गवाह (पी.डब्ल्यू.-2 और पी.डब्ल्यू.-3) अविश्वसनीय या सिखाए-पढ़ाए गए थे। इसका मुकाबला करने के लिए, विद्वान ए.जी.ए. ने बाल गवाहों पर कानून और सिखाई-पढ़ाई गई गवाही का पता लगाने के लिए स्थापित परीक्षणों का उल्लेख किया।

35. भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में, "साक्ष्य अधिनियम") किसी गवाह को एक सक्षम गवाह मानने के लिए निर्धारक कारक के रूप में कोई विशेष आयु निर्धारित नहीं करता है। इसके विपरीत, साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 यह परिकल्पना करती है कि सभी व्यक्ति गवाही देने के लिए सक्षम होंगे, जब तक कि न्यायालय यह न माने कि उन्हें कम आयु, अत्यधिक बुढ़ापे, बीमारी - चाहे वह मस्तिष्क की हो, या उसी प्रकार के किसी अन्य कारण से उनसे पूछे गए प्रश्नों को समझने या उन प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने से रोका गया है। कम आयु के बच्चे को गवाही देने की अनुमति दी जा सकती है, यदि उसमें प्रश्नों को समझने और उनके तर्कसंगत उत्तर देने की बौद्धिक क्षमता है।

36. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'दतू रामराव सखारे बनाम महाराष्ट्र राज्य' (1997) 5 एस.सी.सी. 341 में प्रतिवेदित यह अभिनिर्धारित किया कि जब तक एक बाल गवाह गवाही देने के लिए सक्षम पाया जाता है, अर्थात्, उस पर रखे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है, ऐसे गवाह की गवाही को साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के संदर्भ में साक्ष्य के रूप में माना जा सकता है, भले ही उसकी कम आयु हो या किसी शपथ का अभाव हो। विचार किया जाने वाला एकमात्र अतिरिक्त कारक यह है कि गवाह को विश्वसनीय पाया जाना चाहिए, जो किसी अन्य सक्षम गवाह के आचरण को प्रदर्शित करता हो, और सिखाए-पढ़ाए जाने की कोई संभावना न हो। इसने आगे स्पष्ट किया कि ऐसी कोई आवश्यकता या शर्त नहीं है कि किसी बाल गवाह के साक्ष्य पर विचार करने से पहले उसकी संपुष्टि की जानी चाहिए, और किसी भी संपुष्टि का आग्रह केवल एक विवेक का नियम है, जो प्रत्येक वाद के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार है:-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



"5. [...] यदि बाल गवाह तथ्यों की गवाही देने के लिए सक्षम पाया जाता है और विश्वसनीय है, तो ऐसा साक्ष्य दोषसिद्धि का आधार हो सकता है। दूसरे शब्दों में, शपथ के अभाव में भी बाल गवाह के साक्ष्य पर साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के तहत विचार किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसा गवाह प्रश्नों को समझने और उसके तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम हो। बाल गवाह का साक्ष्य और उसकी विश्वसनीयता प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर निर्भर करेगी। बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय न्यायालय को केवल एक ही सावधानी बरतनी चाहिए कि गवाह एक विश्वसनीय गवाह होना चाहिए और उसका आचरण किसी अन्य सक्षम गवाह की तरह होना चाहिए और उसे सिखाए-पढ़ाए जाने की कोई संभावना नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई नियम या प्रथा नहीं है कि दोषसिद्धि को कायम रखने से पहले हर मामले में ऐसे गवाह के साक्ष्य की संपुष्टि की जाए, लेकिन, विवेक के नियम के रूप में न्यायालय हमेशा यह वांछनीय पाता है कि अभिलेख पर मौजूद अन्य भरोसेमंद साक्ष्यों से ऐसे साक्ष्य की संपुष्टि हो।" (बल दिया गया)

37. इसी तरह 'प्रदीप बनाम हरियाणा राज्य' 2023 एससीसी ऑनलाइन एससी 777 में प्रतिवेदित में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बाल गवाह के प्रारंभिक परीक्षण के महत्व पर जोर दिया। इसने अभिनिर्धारित किया कि यद्यपि 12 वर्ष से कम आयु के बाल गवाह को शपथ नहीं दिलाई जा सकती है, फिर भी साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 के अनुसार, यह पता लगाने के लिए बाल गवाह का साक्ष्य दर्ज करने से पहले प्रारंभिक परीक्षण करना विचारण न्यायाधीश का कर्तव्य है कि क्या बच्चा उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और क्या वह उससे पूछे गए प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। इसने अभिनिर्धारित किया कि विचारण न्यायाधीश को अपनी राय और संतुष्टि दर्ज करनी चाहिए कि बाल गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है और यह बताना चाहिए कि उसकी यह राय क्यों है कि बच्चा सच बोलने के कर्तव्य को समझता है। इसने आगे अभिनिर्धारित किया कि प्रारंभिक परीक्षण में बच्चे से पूछे गए प्रश्न भी दर्ज किए जाने चाहिए, ताकि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय की राय की शुद्धता की जांच कर सके। प्रासंगिक प्रेक्षण इस प्रकार हैं:-

"8. धारा 4 की उपधारा (1) के परंतुक के तहत, यह निर्धारित किया गया है कि 12 वर्ष से कम आयु के बाल गवाह के मामले में, जब तक कि उक्त परंतुक द्वारा अपेक्षित संतुष्टि दर्ज नहीं की जाती है, तब तक बाल गवाह को शपथ नहीं दिलाई जा सकती है। इस मामले में, पी.डब्ल्यू.-1

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



अजय के बयान में, यह उल्लेख किया गया है कि साक्ष्य दर्ज करते समय उसकी आयु 12 वर्ष थी। इसलिए, शपथ अधिनियम की धारा 4 का परंतुक इस मामले में लागू नहीं होगा। हालांकि, साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 की आवश्यकता के दृष्टिगत, विद्वान विचारण न्यायाधीश का यह कर्तव्य था कि वह अपनी राय दर्ज करे कि बच्चा उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और वह उससे पूछे गए प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। विचारण न्यायाधीश को अपनी राय भी दर्ज करनी चाहिए कि बाल गवाह सच बोलने के कर्तव्य को समझता है और यह बताना चाहिए कि उसकी यह राय क्यों है कि बच्चा सच बोलने के कर्तव्य को समझता है।

9. यह एक सुस्थापित सिद्धांत है कि बाल गवाह की गवाही की संपुष्टि एक नियम नहीं है बल्कि सावधानी और विवेक का उपाय है। कम आयु का बाल गवाह आसानी से सिखाए-पढ़ाए जाने के प्रति संवेदनशील होता है। हालांकि, अपने आप में यह बाल गवाह के साक्ष्य को अस्वीकार करने का कोई आधार नहीं है। न्यायालय को बाल गवाह के साक्ष्य की सावधानीपूर्वक सूक्ष्म जांच करनी चाहिए। न्यायालय को इस प्रश्न पर अपना विवेक लगाना चाहिए कि क्या बाल गवाह को सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना है। इसलिए, न्यायालय द्वारा बाल गवाह के साक्ष्य की सूक्ष्म जांच देखभाल और सावधानी के साथ की जानी आवश्यक है।

10. किसी नाबालिग का साक्ष्य दर्ज करने से पहले, यह पता लगाने के उद्देश्य से उससे प्रारंभिक प्रश्न पूछना एक न्यायिक अधिकारी का कर्तव्य है कि क्या नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझ सकता है और तर्कसंगत उत्तर देने की स्थिति में है। न्यायाधीश को संतुष्ट होना चाहिए कि नाबालिग प्रश्नों को समझने और उनका जवाब देने में सक्षम है और सच बोलने के महत्व को समझता है। इसलिए, साक्ष्य दर्ज करने वाले न्यायाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। उसे यह पता लगाने के लिए उचित प्रश्न पूछकर नाबालिग का उचित प्रारंभिक परीक्षण करना होता है कि क्या नाबालिग उससे पूछे गए प्रश्नों को समझने में सक्षम है और तर्कसंगत उत्तर देने में सक्षम है। प्रारंभिक प्रश्नों और उत्तरों को दर्ज करने की सलाह दी जाती है ताकि अपीलीय न्यायालय विचारण न्यायालय की राय की शुद्धता की जांच कर सके।" (बल दिया गया)

38. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'रतनसिंह दलसुखभाई नायक बनाम गुजरात राज्य' (2004) 1 एस.सी.सी. 64 में प्रतिवेदित में स्पष्ट किया कि यद्यपि बाल गवाहों को खतरनाक गवाह माना जाता है क्योंकि वे लचीले होते हैं और आसानी से प्रभावित होने, आकार लेने और ढलने के लिए

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



उत्तरदायी होते हैं, फिर भी यह एक स्वीकृत मानदंड है कि, यदि सावधानीपूर्वक सूक्ष्म जांच के बाद उनकी गवाही विश्वास जगाने वाली और सत्य पाई जाती है, तो ऐसे बाल गवाह के साक्ष्य को स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं है। प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार है:-

"7. [...] इस प्रश्न पर निर्णय कि बाल गवाह के पास पर्याप्त बुद्धिमत्ता है या नहीं, मुख्य रूप से विचारण न्यायाधीश पर निर्भर करता है जो उसके व्यवहार, उसकी स्पष्ट बुद्धिमत्ता या उसकी कमी पर ध्यान देता है, और उक्त न्यायाधीश किसी भी ऐसे परीक्षण का सहारा ले सकता है जो उसकी क्षमता और बुद्धिमत्ता के साथ-साथ शपथ की बाध्यता की उसकी समझ को प्रकट करने की प्रवृत्ति रखता हो। हालांकि, विचारण न्यायालय के निर्णय को उच्च न्यायालय द्वारा बाधित किया जा सकता है यदि अभिलेखों में जो संरक्षित है, उससे यह स्पष्ट हो कि उसका निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण था। यह सावधानी आवश्यक है क्योंकि बाल गवाह सिखाए-पढ़ाए जाने के प्रति उत्तरदायी होते हैं और अक्सर एक काल्पनिक दुनिया में रहते हैं। यद्यपि यह एक स्थापित सिद्धांत है कि बाल गवाह खतरनाक गवाह हैं क्योंकि वे लचीले होते हैं और आसानी से प्रभावित होने, आकार लेने और ढलने के लिए उत्तरदायी होते हैं, लेकिन यह भी एक स्वीकृत मानदंड है कि यदि उनके साक्ष्य की सावधानीपूर्वक सूक्ष्म जांच के बाद न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि इसमें सत्य की छाप है, तो बाल गवाह के साक्ष्य को स्वीकार करने के रास्ते में कोई बाधा नहीं है।"

39. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'पंछी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य' (1998) 7 एस.सी.सी. 177 में प्रतिवेदित में अभिनिर्धारित किया कि एक बाल गवाह के साक्ष्य को सीधे तौर पर खारिज नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि साक्ष्य का सावधानीपूर्वक और अधिक सतर्कता के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चा दूसरों द्वारा उसे जो बताया जाता है उससे प्रभावित होने के प्रति संवेदनशील होता है और आसानी से सिखाए-पढ़ाए जाने का शिकार हो जाता है। प्रासंगिक प्रेक्षण इस प्रकार हैं:-

"11. श्री आर.के. जैन, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने तर्क दिया कि पी.डब्ल्यू. 1 की गवाही पर भरोसा करना बहुत जोखिम भरा है, क्योंकि वह एक बाल गवाह है। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार, बाल गवाह का साक्ष्य आम तौर पर विश्वास के अयोग्य होता है। लेकिन हम इस दृष्टिकोण से सहमत नहीं हैं कि बाल गवाह का साक्ष्य हमेशा अपूरणीय रूप से कलंकित रहेगा। यह कानून नहीं है कि यदि कोई गवाह बच्चा है, तो उसके साक्ष्य को खारिज कर दिया जाएगा, भले ही वह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



विश्वसनीय पाया जाए। कानून यह है कि बाल गवाह के साक्ष्य का अधिक सावधानीपूर्वक और अधिक सतर्कता के साथ मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि एक बच्चा दूसरों द्वारा उसे जो बताया जाता है उससे प्रभावित होने के प्रति संवेदनशील होता है और इस प्रकार एक बाल गवाह आसानी से सिखाए-पढ़ाए जाने का शिकार हो जाता है।

12. न्यायालयों ने निर्धारित किया है कि बाल गवाह के साक्ष्य पर भरोसा करने से पहले उसकी पर्याप्त संपुष्टि होनी चाहिए। यह कानून की तुलना में व्यावहारिक ज्ञान का एक नियम अधिक है।"

40. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 'सूर्यनारायण बनाम कर्नाटक राज्य' (2001) 9 एस.सी.सी. 129 में प्रतिवेदित में अभिनिर्धारित किया कि एक बाल गवाह का साक्ष्य जो प्रति-परीक्षा की कसौटी पर खरा उतरा है, उसे स्वतः खारिज नहीं किया जाना चाहिए, यदि उसकी गवाही किसी भी दुर्बलता से मुक्त पाई जाती है। इसने दोहराया कि बाल गवाह की गवाही की संपुष्टि एक नियम नहीं है बल्कि सावधानी और विवेक का उपाय है। न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय, न्यायालयों को सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना को खारिज करना चाहिए। हालांकि, अभियोजन पक्ष द्वारा किसी गुप्त उद्देश्य के लिए बाल गवाह को सिखाए-पढ़ाए जाने या उपयोग करने के किसी आरोप के अभाव में, न्यायालयों को अभियुक्त के दोष या निर्दोषता का निर्धारण करने में ऐसे गवाह की विश्वास जगाने वाली गवाही पर भरोसा करना चाहिए। प्रासंगिक प्रेक्षण इस प्रकार है:-

"5. [...] बाल गवाह के साक्ष्य को स्वतः खारिज नहीं किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय को, विवेक के नियम के रूप में, ऐसे साक्ष्य पर बारीकी से विचार करने की आवश्यकता है और बयानों की गुणवत्ता और इसकी विश्वसनीयता के बारे में आश्वस्त होने पर ही, बाल गवाह के बयान को स्वीकार करके दोषसिद्धि को आधार बनाना चाहिए। पी.डब्ल्यू. 2 के साक्ष्य को केवल उसकी कम आयु होने के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। पी.डब्ल्यू. 2 के बाल गवाह होने का तथ्य न्यायालय से यह अपेक्षा करेगा कि वह उसकी गवाही की देखभाल और सावधानी के साथ संवीक्षा करे। यदि यह दिखाया जाता है कि वह प्रति-परीक्षा की कसौटी पर खरी उतरी है और उसके साक्ष्य में कोई दुर्बलता नहीं है, तो अभियोजन पक्ष केवल उसकी गवाही के आधार पर दोषसिद्धि का सही दावा कर सकता है। बाल गवाह की गवाही की संपुष्टि कोई नियम नहीं है

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



बल्कि सावधानी और विवेक का उपाय है। बाल गवाह के बयान में कुछ विसंगतियों को गवाही खारिज करने का आधार नहीं बनाया जा सकता है। गवाही में विसंगतियां, यदि तात्त्विक विवरणों में नहीं हैं, तो उस बाल गवाह की गवाही को विश्वसनीयता प्रदान करेंगी जो सामान्य परिस्थितियों में, उसने जो देखा उसे उसके साथ मिलाना चाहेगी जो उसे लगता है कि उसने देखा होगा। बाल गवाह के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय, न्यायालयों को बच्चे को सिखाए-पढ़ाए जाने की संभावना को खारिज करने की आवश्यकता होती है। अभियोजन के गुप्त उद्देश्यों के लिए बाल गवाह को सिखाए-पढ़ाए जाने या उसका उपयोग करने के संबंध में किसी भी आरोप के अभाव में, न्यायालयों के पास अभियुक्त को दोषी ठहराने या न ठहराने के प्रयोजनों के लिए ऐसे गवाह की विश्वास जगाने वाली गवाही पर भरोसा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है।" (बल दिया गया)

41. इस न्यायालय ने 'मध्य प्रदेश राज्य बनाम रमेश' (2011) 4 एस.सी.सी. 786 में प्रतिवेदित में एक बाल गवाह के साक्ष्य के मूल्यांकन से संबंधित सिद्धांतों को निम्नानुसार टिप्पणी किया:-

(i) सबसे पहले, इसने अभिनिर्धारित किया कि एक बाल गवाह को शपथ पर साक्ष्य देने की पवित्रता और उससे पूछे जा रहे प्रश्नों के अर्थ को समझने में सक्षम होना चाहिए। बाल गवाह के साक्ष्य से यह पता चलना चाहिए कि वह सही और गलत के बीच भेद करने में सक्षम था, और न्यायालय साक्ष्य अधिनियम की धारा 165 के संदर्भ में प्रति-परीक्षा के माध्यम से या बच्चे से प्रश्न पूछकर या बच्चे के साक्ष्य या गवाही से ही इसे निर्धारित करके एक गवाह के रूप में उसकी उपयुक्तता का पता लगा सकता है। प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार है:-

"11. एक बच्चे के साक्ष्य से यह प्रकट होना चाहिए कि वह सही और गलत के बीच भेद करने में सक्षम था और न्यायालय प्रति-परीक्षा से यह पता लगा सकता है कि क्या बचाव पक्ष का वकील यह इंगित करने के लिए कुछ भी ला सकता है कि बच्चा सही और गलत के बीच अंतर नहीं कर सकता था। न्यायालय उससे प्रश्न पूछकर एक गवाह के रूप में उसकी उपयुक्तता का पता लगा सकता है और भले ही ऐसे कोई प्रश्न न पूछे गए हों, यह उसके साक्ष्य से इकट्ठा किया जा सकता है कि क्या वह जो कह रहा था उसके निहितार्थ को पूरी तरह से समझता था और क्या वह एक कड़ी प्रति-परीक्षा का सामना करने में अविश्वसनीय साबित हुआ। एक बाल गवाह को शपथ पर साक्ष्य देने की पवित्रता और उससे पूछे जा रहे प्रश्नों के अर्थ को समझने में सक्षम होना चाहिए।

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



(देखें: हिम्मत सुखदेव वाहुरवाघ बनाम महाराष्ट्र राज्य (2009) 6 एस.सी.सी. 712)" (बल दिया गया)

(ii) दूसरा, यदि बच्चे का साक्ष्य सुधार या अलंकरण के बिना अपराध की प्रासंगिक घटनाओं को स्पष्ट करता है, और वह न्यायालय का विश्वास जगाता है, तो उसके बयान को किसी भी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार है:-

"12. 'उत्तर प्रदेश राज्य बनाम कृष्ण मास्टर (2010) 12 एस.सी.सी. 324' में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि ऐसा कोई विधिक सिद्धांत नहीं है कि यह अकल्पनीय है कि एक कम आयु का बच्चा अपनी स्मृति में तथ्यों को संक्षेप में नहीं बता पाएगा। एक बच्चा हमेशा उन असामान्य घटनाओं के प्रति ग्रहणशील होता है जो उसके जीवन में घटित होती हैं और उन घटनाओं को अपने शेष जीवन के लिए कभी नहीं भूलेगा। बच्चा भविष्य में इसके बारे में पूछे जाने पर सावधानीपूर्वक और ठीक से संक्षेप में बताने में सक्षम हो सकता है। यदि बच्चा अपराध की प्रासंगिक घटनाओं को बिना किसी सुधार या अलंकरण के स्पष्ट करता है, और वही न्यायालय का विश्वास जगाता है, तो उसके बयान को किसी संपुष्टि की आवश्यकता नहीं है। कम आयु का बच्चा किसी भी व्यक्ति के प्रति कोई द्वेष या दुर्भावना रखने में असमर्थ होता है। इसलिए, न्यायालय को संतुष्ट करने के लिए अभिलेख पर कुछ ऐसा होना चाहिए कि घटना की तिथि और बाल गवाह के साक्ष्य दर्ज करने के बीच कुछ गलत हो गया था जिसके कारण गवाह गंभीर प्रकृति के मामले में अभियुक्त को झूठा फंसाना चाहता था।" (बल दिया गया)

(iii) तीसरा, भले ही न्यायालयों को यह लगे कि बाल गवाह को सिखाया-पढ़ाया गया था, फिर भी बाल गवाह के बयान पर भरोसा किया जा सकता है यदि सिखाए-पढ़ाए गए हिस्से को बिना सिखाए-पढ़ाए गए हिस्से से अलग किया जा सकता है और शेष बिना सिखाया-पढ़ाया गया हिस्सा विश्वास जगाता है। ऐसे मामलों में, बिना सिखाए-पढ़ाए गए हिस्से पर विश्वास किया जा सकता है या कम से कम एक पक्षद्रोही गवाह के मामले की तरह संपुष्टि के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है। प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार है:-

"13. एक बाल गवाह के बयान के एक हिस्से पर, भले ही उसे सिखाया-पढ़ाया गया हो, भरोसा किया जा सकता है, यदि सिखाए-पढ़ाए गए हिस्से को बिना सिखाए-पढ़ाए गए हिस्से से अलग किया जा सकता है, यदि ऐसा शेष बिना सिखाया-पढ़ाया गया हिस्सा विश्वास जगाता है। ऐसी

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



स्थिति में बिना सिखाए-पढ़ाए गए हिस्से पर विश्वास किया जा सकता है या कम से कम पक्षद्रोही गवाह के मामले की तरह संपुष्टि के उद्देश्य से विचार किया जा सकता है। (देखें: गगन कनौजिया बनाम पंजाब राज्य (2006) 13 एस.सी.सी. 516)" (बल दिया गया)

(iv) अंततः, इसने अभिनिर्धारित किया कि क्या बच्चे को सिखाया-पढ़ाया गया है या नहीं, इसका अनुमान उसके बयान की विषय-वस्तु से निकाला जा सकता है। यदि किसी बाल गवाह का बयान न्यायालय का विश्वास जगाता है और उसमें कोई अलंकरण या सुधार नहीं है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है। बाल गवाह के साक्ष्य का अधिक सावधानी के साथ और अधिक सतर्कता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि वह सिखाए-पढ़ाए जाने के प्रति संवेदनशील होता है। केवल उस स्थिति में जब अभिलेख पर यह दिखाने के लिए साक्ष्य हो कि एक बच्चे को सिखाया-पढ़ाया गया है, न्यायालय उसके बयान को आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज कर सकता है और संपुष्टि की तलाश कर सकता है। प्रासंगिक टिप्पणी इस प्रकार है:-

"14. उपरोक्त के दृष्टिगत, इस मुद्दे पर कानून को इस प्रभाव से संक्षेपित किया जा सकता है कि एक बाल गवाह के बयान को संपुष्टि की आवश्यकता हो सकती है, लेकिन यदि उसका बयान न्यायालय का विश्वास जगाता है और उसमें कोई अलंकरण या सुधार नहीं है, तो न्यायालय उसके साक्ष्य पर भरोसा कर सकता है। बाल गवाह के साक्ष्य का अधिक सावधानी के साथ और अधिक सतर्कता से मूल्यांकन किया जाना चाहिए क्योंकि वह सिखाए-पढ़ाए जाने के प्रति संवेदनशील होता है। केवल उस स्थिति में जब अभिलेख पर यह दिखाने के लिए साक्ष्य हो कि एक बच्चे को सिखाया-पढ़ाया गया है, न्यायालय उसके बयान को आंशिक या पूर्ण रूप से खारिज कर सकता है। हालांकि, बच्चे को सिखाया-पढ़ाया गया है या नहीं, इसका अनुमान उसके बयान की विषय-वस्तु से निकाला जा सकता है।" (बल दिया गया)

42. कानून की उपरोक्त व्याख्या से, यह स्पष्ट है कि एक बाल गवाह के साक्ष्य को सभी उद्देश्यों के लिए किसी भी अन्य गवाह के समान स्तर पर माना जाता है जब तक कि बच्चा गवाही देने के लिए सक्षम पाया जाता है। एकमात्र एहतियात, जो न्यायालय को एक बाल गवाह के साक्ष्य का आकलन करते समय बरतनी चाहिए, वह यह है कि बच्चों के सिखाए-पढ़ाए जाने का शिकार होने की संवेदनशीलता के कारण ऐसा गवाह विश्वसनीय होना चाहिए। हालांकि, इसका अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि किसी बच्चे के साक्ष्य को

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



मामूली सी विसंगति पर सीधे खारिज कर दिया जाना चाहिए, बल्कि आवश्यकता यह है कि इसका बड़ी सतर्कता के साथ मूल्यांकन किया जाए। एक बाल गवाह की गवाही का मूल्यांकन करते समय न्यायालयों को यह आकलन करना आवश्यक है कि क्या ऐसे गवाह का साक्ष्य उसकी स्वैच्छिक अभिव्यक्ति है और दूसरों के प्रभाव से उत्पन्न नहीं हुआ है तथा क्या गवाही विश्वास जगाती है। साथ ही, किसी को यह ध्यान रखना चाहिए कि किसी बाल गवाह की गवाही पर भरोसा करने से पहले उसकी संपुष्टि की आवश्यकता का कोई नियम नहीं है। संपुष्टि का आग्रह केवल सावधानी और विवेक का एक उपाय है जिसका प्रयोग न्यायालय वाद के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में आवश्यक समझे जाने पर कर सकते हैं।

43. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह भी प्रस्तुत किया गया है कि नक्शा-नजरी में चूक और पी.डब्ल्यू.-6 की गवाही में मामूली विरोधाभास अत्यधिक असमर्थनीय है। अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता इस तथ्य पर बहुत अधिक भरोसा करते हैं कि विवेचना अधिकारी नक्शा-नजरी में कटी हुई फसलों, दरांती, या सटीक रास्तों को दर्शाने में विफल रहा। विद्वान ए.जी.ए. ने 'जगदीश नारायण बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एआईआर 1996 सर्वोच्च न्यायालय 3136' में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थापित विधि पर भरोसा किया, जहां माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया कि एक विवेचना अधिकारी द्वारा नक्शा-नजरी तैयार करने में प्रक्रियात्मक खामियों या मामूली चूकों, जैसे कि सटीक स्थानों या कृषि उपकरणों को चिह्नित करने में विफलता का उपयोग चक्षुदर्शी गवाहों की विश्वसनीय और बेदाग मौखिक गवाही को खारिज करने के लिए नहीं किया जा सकता है। ऐसे दोषों को घातक विरोधाभासों के बजाय केवल विवेचनात्मक चूक माना जाना चाहिए, जो अभियोजन पक्ष के मामले को दूषित कर देंगे।

44. न्यायालय ने विचारण न्यायालय के अभिलेखों, गवाहियों और भौतिक प्रदर्शनों की गहन जांच करने के बाद, यह प्रेक्षण किया कि कृषि क्षेत्र में चक्षुदर्शी गवाहों पी.डब्ल्यू.-2 (संजीव कुमार) और पी.डब्ल्यू.-3 (कु. अंजू) की उपस्थिति पूरी तरह से स्वाभाविक और विश्वसनीय है, क्योंकि वे अपनी बहन के साथ चारा काटने गए थे। अभियुक्त द्वारा सीमा का हाथ पकड़ने और उसके पेट में जानलेवा गोली चलाने के संबंध में उनकी गवाही कड़ी प्रति-

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



परीक्षा के दौरान पूरी तरह से अडिग रही। न्यायालय ने ध्यान दिया कि इतनी उच्च विश्वसनीयता वाले मौखिक साक्ष्य से जुड़े मामलों में, नक्शा-नजरी में मामूली प्रक्रियात्मक चूक, जैसे दरांती या कटी हुई गड़्डियों का नक्शा न बनाना, अभियोजन पक्ष के संस्करण के मूल को कमजोर नहीं करते हैं। पैर की दुर्बलता के कारण पूर्ण शारीरिक अक्षमता के बचाव के संबंध में, न्यायालय ने टिप्पणी किया कि यद्यपि गवाहों ने स्वीकार किया कि अभियुक्त थोड़ा लंगड़ा कर चलता था, यह स्पष्ट रूप से नकारा गया कि उसे लकवा मार गया था या अपराध स्थल से भागने के एड्रेनालाईन के तहत दौड़ने में असमर्थ था। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि शारीरिक विकलांगता एक घातक देशी तमंचे को चलाने और फायर करने की क्षमता में बाधा नहीं डालती है। मृत्यु का कारण मृत्यु-पूर्व चोटें दिखाया गया है जैसा कि मेडिकल रिपोर्ट द्वारा सुझाया गया है।

45. राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता और वित्तीय विवाद का सिद्धांत, जिसमें बकाया ऋण या गांव की पार्टी-बंदी शामिल है, को इस कारण से खारिज किया जाना उचित है क्योंकि यह एक दुधारी तलवार है, जो अभियुक्त को अपराध करने के लिए समान रूप से मजबूत उद्देश्य प्रदान करता है, विशेष रूप से मृतका के साथ अपीलकर्ता के दुर्व्यवहार के इतिहास को देखते हुए जिसके लिए सार्वजनिक रूप से माफी मांगी गई थी। पी.डब्ल्यू.-7 के चिकित्सीय निष्कर्ष पूरी तरह से अभियोजन पक्ष की समय-सीमा के साथ मेल खाते हैं, और शव के हाथों और पैरों पर कीचड़ की उपस्थिति ने इस तथ्य को और पुष्ट कर दिया कि संघर्ष और गोलीबारी बताए गए अनुसार कीचड़दार, बारिश से प्रभावित खेत में हुई थी।

46. परिणामस्वरूप, इस न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा पारित सुतर्कित निर्णय में कोई अवैधता, दुर्बलता या विकृति नहीं मिलती है। अभियोजन पक्ष ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अंतर्गत अभियुक्त-अपीलकर्ता के अपराध को किसी भी युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित किया है।

47. विद्वान अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या 7, बुलंदशहर द्वारा लगाए गए अर्थदंड के साथ-साथ आजीवन कारावास की सजा और दोषसिद्धि की एतद्वारा पुष्टि की जाती है और उसे बरकरार रखा जाता है। यदि अपीलकर्ता जमानत पर है, तो उसके जमानत बंधपत्र

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



रद्द किए जाते हैं और उसे तत्काल संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया जाता है।

48.अतः वर्तमान आपराधिक अपील तदनुसार **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति हरवीर सिंह) (न्यायमूर्ति सिद्धार्थ)

3 जून, 2026

गुरप्रीत सिंह

“अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”